श्री वीरेन्द्र प्रसाद (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में बीड़ी मजदूरों की संख्या करीब 30 लाख है जिसमें पचास हजार बिहार राज्य में है, दस हजार नालन्दा जिले में हैं। प्रत्येक राज्य में इस सम्बन्ध में अलग-अलग कानून एवं नियम हैं। इस रोजगार में भारी संख्या में लगे मजदूरों को देखते हुए उसमें एकरूपता लानी चाहिये। समान काम के लिए समान मजदूरी के आधार पर मजदूरी तय करने में सरकार को पहल करनी चाहिये। मजदूरों की व्यवस्था में सुधार हो, मालिकों के शोषण से इनको बचाने के लिए वर्तमान कानून में संशोधन करना चाहिये। महंगाई भत्ता समय पर मिले, इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। नालन्दा जिले में अभी तक सरकारी आश्वासन के बावजूद भी 22 पैसे महंगाई भत्ता मजदूरों को नहीं मिल पाया। मजदूरों पर दबाव डालने के लिए मालिक काम का घंटा कम देते हैं, मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं करते।

सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। बीड़ी मजदूरों को आइडेंटिटी कार्ड मिलना चाहिये। डाक्टर को बीड़ी गोदामों में जहां मजदूर काम करते हैं, वहां जाकर मजदूरों के स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिये और दवाई देनी चाहिये। इसकी भी व्यवस्था सरकार स्वयं करे या मालिकों से कराये।

(ii) IMPENDING CLOSURE OF INDUSTRIES IN SAURASHTRA REGION OF GUJARAT DUE TO SHORTAGE OF STEAM COAL ARISING FROM NON-AVAILABILITY OF WAGONS

श्री धर्मसिंहभाई पटेल (पोरबन्दर) : अध्यक्ष महोदय, लोकसभा के नियम 377 के अन्तर्गत मैं लोक महत्व के विषय "स्टीम कोयले के वैगनों के अभाव से गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के पोरबन्दर—राणावाव—मोरबी—राजकोट, भावनगर—जामनगर, जूनागढ़ वगैरह क्षेत्रों में उद्योगों का बन्द होने" के बारे में एक संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहता हूं।

स्टीम कोयले के वैगनों के अभाव से हमारे गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में निम्नलिखित पांच उद्योगों या कारखानों का उत्पादन बन्द हो गया है या हो रहा है।

(1) सौराष्ट्र सीमेंट एंड कैमिकल इंडस्ट्रीज लि० राणावाव, जिला जूनागढ़ (गुजरात) की प्रतिदिन 2600 टन सीमेंट उत्पादन करने वाली इस सीमेंट फैक्टरी में से प्रति दिन 1000 टन सीमेंट उत्पादन करती हुई एक कीलन स्टीम कोयले के वैगनों के अभाव से 27-3-78 के बन्द हो गई है, इससे 700 मजदूर बेकार हो गये हैं।

इस समय फैक्टरी को प्रतिदिन 500 टन कोयले की जरूरत होती है। इसलिये फरवरी और मार्च से कोयले की तंगी या कमी प्रवर्तमान थी। अनामत कोयले का स्टाक भी खत्म हो गया। सीमेंट का पूर्ण उत्पादन करने के लिए प्रति दिन 500 टन कोयले के हिसाब से प्रति माह रेलवे के 7 वैगनों की एक रैक की जरूरत पड़ती है। राणावाव कोयले के क्षेत्र से बहुत दूरी पर है, इस सीमेंट फैक्टरी को मध्य प्रदेश की खदानों में से कोयला वैगन आते हैं। सीमेंट उत्पन्न करती, इस फैक्टरी की कीलन एक दिन बन्द रहे और दूसरे दिन चालू करें तो कम्पनी को प्रति दिन एक लाख रुपये का नुकसान होता है। क्योंकि कीलन में हुई ईंटें गिर जाती हैं, इन्हें फिर लगाना पड़ता है। श्री सौराष्ट्र सीमेंट एंड कैमिकल इंडस्ट्रीज

लि०, राजावाव के मैनेजमैंट ने भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय को, कलकत्ता भावनगर, बम्बई के रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को और गुजरात सरकार को पत्रों से, तारों से कई बार ध्यान खींचा है, तो भी इसका कोई परिणाम आया नहीं है। इससे यह सीमेंट उद्योग को, मजदूरों को और सरकार को नुकसान होता है, और सीमेंट की सप्लाई कम हो जाने से लोगों को मुश्किलें बढ़ जाती हैं।

(2) स्टीम कोयले के अभाव से गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के पोरबन्दर शहर में स्थित श्री जगदीश आयल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि०, पोरबन्दर की वनस्पति उद्योग की फैक्टरी को भी प्रति दिन 10 टन के हिसाब से प्रति मास 300 टन स्टीम कोयले की जरूरत पड़ती है। इस इंडस्ट्री को 1-9-77 से 20-2-78 के दौरान सिर्फ 377 टन कोयला मिला था। अब यह वनस्पति इंडस्ट्री भी बन्द हो गई है। इसके मैनेजमैंट ने तारीख 13-2-78 से चीफ आपरेटिंग सुपरिन्टैंडेंट, वैस्टर्न रेलवे, बम्बई को तारीख 8-2-78 से ज्वाइन्ट डायरेक्टर ट्रांसपोर्टेशन (कोल), ईस्टर्न रेलवे, कलकत्ता को पत्रों से और 7-2-78 से तार से ज्वाइंट डायरेक्टर ट्रांसपोर्टेशन (कोल) को कोयले के वैगनों को तुरन्त भेजने के बारे में ताकीद की थी तो भी रेलवे तंत्र ने कुछ किया नहीं।

(3) इसी तरह पोरबन्दर के कैमिकल के बड़े उद्योग श्री सौराष्ट्र कैमिकल्स लि०, पोरबन्दर की भी स्टीम कोयले से बनती हुई बिजलीघर को भी तंगी हो गई है। इससे यह बड़ा उद्योग भी बन्द होने की स्थिति में आ गया है।

(4) सौराष्ट्र प्रदेश के मोरबी शहर में रूफिंग—टाइल्स बड़े पैमाने पर बन रही हैं, तो इन उद्योगों को भी जनवरी, 78 से स्टीम कोयले के वैगन न मिलने से बहुत रूफिंग टाइल्स के कारखाने बन्द हो गये हैं और प्रतिदिन बन्द हो रहे हैं। इससे 5,000 मजदूरों की रोजी का सवाल उठा है। इस उद्योग के एसोसियेशन ने भी भारत सरकार और गुजरात सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, तो भी कुछ नहीं हुआ है।

(5) थोड़े ही दिनों पहले पोरबन्दर की महाराणा कपड़ा-मिल स्टीम कोयले के अभाव से बन्द हो गई थी, फिर थोड़े कोयले के वैगन आने से चालू हो गई है, परन्तु अब इन्हें पूरे कोयले के वैगन मिलना जरूरी है ताकि नियमित रूप से चल सके।

तो हमारे उल्लिखित उद्योगों को तुरन्त कोयले के वैगन प्राथमिकता से मिलें, ऐसा प्रबन्ध करने के लिये भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय, और ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग और उद्योग मंत्रालय से मैं प्रार्थना करता हूं।

SHRI RAGHAVJI (Vidisha): Sir, I have also given a notice under Rule 377.

MR. SPEAKER: All the notices received are considered; if you give today, it will be considered for tomorrow.

श्री राघवजी : चार दिन पहले दिया है।

12.45 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1978-79—Contd.

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING, AND MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION—Contd.